

व्यक्तिगत उपभोक्ताओं, व्यवसायों और सभी प्रकार के संगठनों की तरह, बैंकों को निधि ट्रांसफर करने और इंटर-बैंक ट्रांज़ैक्शन जैसे कि अन्य बैंकों से उधार लेने और अन्य बैंकों और ग्राहक ट्रांज़ैक्शन में उधार लेने लेनदेन खुद की प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। बैंक से बैंकों के रूप में, रिज़र्व बैंक इस भूमिका को पूरा करता है।

वित्तीय इन्क्लूजन एंड डेवलपमेंट टेस्ट डमी 2812 01 अपडेट सीनेरिया

अपनी स्थापना से ही, भारतीय रिज़र्व बैंक ने सरकार के बैंकिंग लेनदेन को मैनेज करने का पारंपरिक केंद्रीय बैंकिंग कार्य किया है। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत केंद्र सरकार को भारत में अपने सभी पैसे, प्रेषण, एक्सचेंज और बैंकिंग ट्रांज़ैक्शन के साथ रिज़र्व बैंक को सौंपा जाना आवश्यक है। रिज़र्व बैंक, किसी समझौते द्वारा, राज्य सरकारों के बैंकर के रूप में भी कार्य कर सकता है।

रिज़र्व बैंक के दायित्वों को अच्छी तरह से परिभाषित किया गया है और सरकारों को कई बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता है। सरकार के बैंकर के रूप में, रिज़र्व बैंक विभिन्न सरकारी विभागों की ओर से पैसे प्राप्त करता है और भुगतान करता है। यह एक अल्पकालिक हित-भरी अग्रिम एक्स सरकारों को प्रदान करता है, उनकी प्राप्तियों में अस्थायी मिसमैचों को पूरा करने के लिए और इसका मतलब है कि एक अग्रिम ऋण। इसके अलावा, पोर्टफोलियो मैनेजर की तरह, यह सरकारों के अतिरिक्त कैश बैलेंस के इन्वेस्टमेंट की व्यवस्था भी करता है। रिज़र्व बैंक सरकार के सलाहकार के रूप में कार्य करता है, जब भी ऐसा करने का अनुरोध किया जाता है, मौद्रिक और बैंकिंग से संबंधित मामलों पर। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें कंसोलिडेटेड निधि, आकस्मिकता निधि और सार्वजनिक खाता से पैसे की प्राप्ति, कस्टडी और डिस्बर्समेंट के लिए नियम बना सकती हैं। खाता रिज़र्व बैंक पर कानूनी रूप से बाध्यकारी हैं क्योंकि इन निधि के खाते रिज़र्व बैंक के पास हैं।

वित्तीय इन्क्लूजन एंड डेवलपमेंट टेस्ट डमी 2812 01 अपडेट सीनेरिया

सरकारों के लिए बैंकिंग कार्य रिज़र्व बैंक के कार्यालयों/शाखाओं में सरकारी बैंकिंग विभागों द्वारा किए जाते हैं। चूंकि इसके 34 स्थानों पर ऑफिस और उप-कार्यालय हैं, इसलिए रिज़र्व बैंक ने अन्य बैंकों को सरकारों की ओर से बैंकिंग व्यवसाय करने के लिए अपने एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया है। रिज़र्व बैंक ने इसके लिए एजेंसी बैंकों को कमीशन का भुगतान किया। केंद्र और राज्यों के सरकारी खातों का अंतिम संकलन केंद्रीय खातों विभाग, नागपुर बैंक के कार्यालय में किया जाता है।

बैंकों को रिज़र्व बैंक के पास कैश रिज़र्व के रूप में अपनी मांग और समय देयताओं का एक हिस्सा बनाए रखना भी आवश्यक है। इस उद्देश्य के लिए, उन्हें रिज़र्व बैंक के साथ करंट खाते बनाए रखना होगा। बैंकों का करंट खाते रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों के बैंकिंग विभागों द्वारा खोला जाता है। सरकारी और बैंक अकाउंट विभाग (डीजीबीए) करंट अकाउंट खोलने के लिए सामान्य दिशानिर्देश जारी करता है।

वित्तीय इन्क्लूजन एंड डेवलपमेंट टेस्ट डमी 2812 01 फूटर